Funds Allocated to J&K States as Plan Assistance

@*30A. SHRI SHABBIR AHMED SALARIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that J&K State is entitled to 90 per cent grant and 10 per cent loan as plan assistance from the Central Government, being one of the eight special category States;

(b) whether it is also a fact that at present the State is being given 30 per cent grant and 70 per cent loan;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, what are the reasons therefor; and

(d) when the State will be allocated funds according to its entitlement?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) No, Sir. Only the Ladakh region of J&K State is entitled for plan assistance in the form of 90% grant and 10% loan.

(b) Yes, Sir, except for the Ladakh region as stated in part (a).

(c) Does not arise.

(d) The State already being allocated funds according to its entitlement.

Environmental Clearance to the Narmada Sardar Sarovar Project

*31. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some organisations have been campaigning against the Narmada Sardar Sarovar Project on the issue of environmental protection; if so, what is the reaction of Government thereto and whether adequate funds would be released for expediting work on this project;

(b) whether Government are also aware that environmental clearance to the Narmada Project has been given after scrutinising all aspects of rehabilitation and aforestation; if so, whether Government stand committed to complete this National project; and

(c) whether the Prime Minister has publicly spoken against the big irrigation projects in his interview in the *Illustrated Weekly of India* issue of August 20-26, 1989 and whether he has changed his opinion since then?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SMT. MANEKA GANDHI): (a) The Government is aware of the campaign against Narmada Sagar and Sardar Sarovar Projects. The Projects were accorded environmental clearance in June 1987, with certain stipulations to safeguard the environment. Provision of the funds for the project is subject to overall availability of resources in the Plan.

(b) and (c) All aspects of rehabilitation and afforestation have been scrutinised. There is no change in the earlier decision. Action on all the environmental aspects is to proceed simultaneously with the engineering works, as stipulated while clearing the project.

भारतीय खाद्य निगम को राजसहायता

*32. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को वित्तीय सहायता के रूप में नियमित रूप से सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम को प्रति वर्ष कितनी-

@Previously Starred Question No. 71, transferred from the 28th December 1989.

कितनी धनराशि राजसहायता के रूप में दी गई ; और

(ग) सरकार भविष्य में इस राशि को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम को (i) खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और उनके निर्गम मूल्य के बीच अंतर अर्थात उपभोक्ता राजसहायता ; (ii) बफर स्टाक रखने की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए खाद्य राजसहायता प्रदान करती है। खाद्य राजसहायता की राशि की मात्रा उठान, खाद्य स्टाक और भाड़ा, ब्याज प्रभारों आदि जैसे अन्य तथ्यों तथा खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य पर निर्भर करती है ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को अदा की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार थी :—

वर्ष	खाद्य राजसहायता की राशि (करोड़ रुपए में)
1986-87 . .	2000
1987-88 . .	2000
1988-89 . .	2200

स्टाफ की संख्या में कमी करने, भारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने, किराए के अलाभकारी और फालतू गोदामों को त्यागने आदि जैसे उपाय कर भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत को कम करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं ।

खाद्य तिलहनों को पिराई की क्षमता

@*32क. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष खाद्य तेलों के उत्पादन का एक नया रिकार्ड स्थापित हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में खाद्य तेलों का उत्पादन अपर्याप्त होने का कारण देश में तिलहनों की पिराई की क्षमता का कम होना तथा पिराई की मशीनरी आधुनिक न होना है ;

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग का आधुनिकिकरण करने तथा इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई प्रोत्साहन नहीं दिए जा रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी, हां ।

(ख) उद्योग की समग्र पिराई क्षमता देश में तिलहनों के कुल उत्पादन को खपाने के लिए पर्याप्त है ।

(ग) सरकार ने तेल पिराई उद्योग को अपग्रेड करने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए सीमा शुल्क की रियायती-दर पर कुछ उपकरण आयात करने की अनुमति दी हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Loopholes and Flaws in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987

*33. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some Women's Organisations have brought to the notice of Government some loopholes and flaws in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987; and

@पूर्वत: तारांकित प्रश्न 74, 28 दिसम्बर, 1989 से स्थानान्तरित ।